जेनरेटिव एआई बनी कारोबार की नई धड़कन

एआई का दैनिक उपयोग 17% बढ़ा, 46% नेता कर रहे रोज़ाना इस्तेमाल

नई दिल्ली. जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब प्रयोग की सीमा से निकलकर कारोबार जगत के दैनिक कामकाज का हिस्सा बन गई है. व्हार्टन ह्यूमन-एआई रिसर्च की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, करीब 46 प्रतिशत कारोबारी नेता रोज़ाना जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. वहीं, 80 प्रतिशत से अधिक नेता हर सप्ताह किसी न किसी रूप में इसका उपयोग करते हैं.

रिपोर्ट बताती है कि वरिष्ठ पदों पर बैठे अधिकारियों में एआई को लेकर अधिक उत्साह है. उपाध्यक्ष स्तर या उससे ऊपर के 56 प्रतिशत अधिकारी मानते हैं कि उनकी संस्था अन्य कंपनियों की तुलना में तेज़ी से त्नद्गठ्ठ ढ्ढ अपना रही है, जबकि मध्य स्तर के केवल 28 प्रतिशत प्रबंधक ऐसा सोचते हैं.

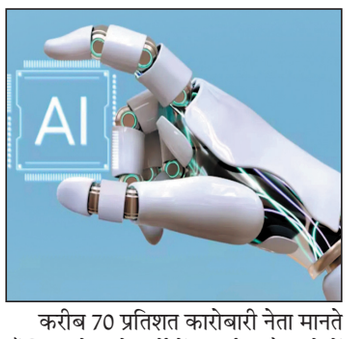

करीब 70 प्रतिशत कारोबारी नेता मानते हैं कि आने वाले वर्षों में एआई उनके उद्योगों पर गहरा या क्रांतिकारी असर डालेगी, वहीं 88 प्रतिशत संगठन अगले वर्ष एआई पर खर्च बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. अब तक 67 प्रतिशत कंपनियों में वरिष्ठ प्रबंधन सीधे एआई परियोजनाओं में शामिल है और 60 प्रतिशत कंपनियों ने चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किए हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, एआई अपनाने की प्रक्रिया असमान है — आईटी और परचेजिंग विभाग इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं, जबकि मार्केटिंग, बिक्री और संचालन विभाग पिछड़ रहे हैं. बड़ी कंपनियां अब छोटे और मध्यम उद्यमों की बराबरी कर रही हैं, लेकिन तकनीकी, टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर अब भी मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल उद्योगों से आगे हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि अब शुरुआती उत्साह के स्थान पर जवाबदेही और वास्तविक परिणाम पर ज़ोर दिया जा रहा है. करीब तीन-चौथाई नेता लाभप्रदता और उत्पादकता जैसे ठोस मानकों से एआई निवेश का मूल्यांकन कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 'अब एआई निवेश का नया सूत्र है — बजट अनुशासन और ऋह्वढ्ढ पर सख्त नज़र.'

तीन-चौथाई कंपनियों को पहले से ही सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, जबकि चार में से पाँच संगठन आने वाले दो से तीन वर्षों में और बेहतर लाभ की उम्मीद कर रहे हैं.

> रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि एआई अपनाने की सफलता अब मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण और स्पष्ट भूमिका निर्धारण पर निर्भर करेगी. इसका कहना है कि 'टैलेंट, ट्रेनिंग और भरोसेमंद गवर्नेंस जैसे मानवीय पहलू सीधे तौर पर एआई अपनाने की गति और सफलता को प्रभावित करते हैं.' महज़ एक वर्ष में ही एआई प्रयोगों से निकलकर संगठनों की मुख्य कार्य प्रणाली का हिस्सा बन गई है. डेटा विश्लेषण, दस्तावेज़ सारांश और लेखन जैसे कार्यों में इसका उपयोग सबसे अधिक प्रभावी साबित हो रहा है. रिपोर्ट निष्कर्ष देती है — 'टीमें जब अपने मौजूदा कार्यप्रवाह में एआई को शामिल कर रही हैं, तो उन्हें वास्तविक और मापने योग्य लाभ मिल रहे हैं.'

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने पेश किया नया फंड

मुंबई, 04 नवंबर. जीवन बीमा कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) के लिए एक नया फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ बीएसई 500 एन्हांस्ड वैल्यू 50 इंडेक्स फंड, पेश किया है. कंपनी ने मंगलवार को फंड की घोषणा करते हुए कहा कि इस फंड का उद्देश्य ग्राहकों को देश की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में भागीदारी के लिए मंच प्रदान करना है. यह फंड उन शेयरों पर फोकस करेगा जो सैद्धांतिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन फिलहाल अपनी वास्तविक क्षमता से कम रिटर्न दे रहे हैं. कंपनी ने कहा कि यह इंडेक्स फंड ग्राहकों को उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.

नए युग में प्रवेश कर रही भारत की ऊर्जा-यात्रा : हरदीप सिंह

अब तक 8,000 किमी से अधिक क्षेत्र में सिस्मिक सर्वे पूरा

सात सेडिमेंट्री बेसिन में अत्याधुनिक तकनीक से खोज जारी

नई दिल्ली, 4 नवंबर. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'मिशन अन्वेषण' की शुरुआत के साथ ही भारत की ऊर्जा यात्रा एक नए युग में प्रवेश कर गई है. यह मिशन देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सिस्मिक मैपिंग प्रोग्राम है, जिसे बीते वर्ष अक्टूबर में 792 करोड़ रुपये के निवेश से लॉन्च किया गया था.

मंत्री पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा करते हुए देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि भारत आज भी अपनी ऊर्जा की 80 प्रतिशत जरूरत तेल और गैस से पूरी करता है. दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, अनुमान है कि अगले दो दशकों में ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत की होगी. इस भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए ही देश आंतरिक बदलावों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

मैपिंग और प्रगति का लक्ष्य- 'मिशन अन्वेषण' का उद्देश्य देश की जमीन और समुद्र के नीचे छिपी दौलत का पता लगाना है. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश भर में 20,000 ग्राउंड लाइन किलोमीटर से अधिक की मैपिंग करना है. पुरी ने जानकारी दी कि अभी तक कुल 8,000 ग्राउंड-लाइन किलोमीटर का सर्वेक्षण किया जा चुका है.

इस मिशन के तहत राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर कृष्णा-गोदावरी बेसिन की गहराइयों तक सात सेडिमेंट्री बेसिन की सबसे उन्नत सिस्मिक टेक्नोलॉजी से स्टडी की जा रही है. इसका लक्ष्य भूमिगत रिजर्व की कहानी को कैप्चर, प्रोसेस और इंटरप्रेट करना है.

लक्ष्य : ऊर्जा में आत्मनिर्भरता

मंत्री पुरी ने स्पष्ट किया कि 'मिशन अन्वेषण' का लक्ष्य नए तेल और गैस फील्ड्स को खोजकर घरेलू उत्पादन को मजबूत बनाना है. इससे महंगे आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने का शक्तिशाली लक्ष्य पूरा होगा.

कोयला मंत्रालय
Ministry of Coal
सत्यमेव जयते
भारत सरकार

कोयला मंत्रालय ने विशेष अभियान में रचा कीर्तिमान

स्वच्छता, नवाचार और पारदर्शिता में लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां

वेस्टर्न कोलफील्ड्स में पूरी तरह महिला टीम ने संभाला वित्त विभाग.

नई दिल्ली. कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार के विशेष अभियान 5.0 के तहत अपने तय लक्ष्यों से अधिक उपलब्धियां हासिल की हैं. यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में कार्यकुशलता, स्वच्छता और अभिलेख प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना था.

मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान के दौरान 56.85 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ और 1.28 लाख से अधिक फाइलों का निस्तारण किया गया. यह अभियान केवल प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें रचनात्मकता, स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी को भी प्राथमिकता दी गई.

अभियान के अंतर्गत कोयला मंत्रालय के अधीन आने वाली कंपनियां — कोल इंडिया लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स, सेंट्रल कोलफील्ड्स, महानदी कोलफील्ड्स और ईस्टर्न कोलफील्ड्स — ने नवाचार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले अनेक कार्य किए.

कोल इंडिया लिमिटेड ने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संड्डतुलन के लिए अपने आवासीय परिसर में योग और ध्यान कक्ष की शुरुआत की. वहीं, वेस्टर्न कोलफील्ड्स के मुख्यालय में पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित 'लागत एवं बजट अनुभाग' की स्थापना की गई, जो वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है.

> सेंट्रल कोलफील्ड्स के मगध-संघमित्रा क्षेत्र में सफाई अभियान के दौरान एकत्र किए गए अपशिष्ट से सात फुट ऊँचा कोयला मजदूर का शिल्प तैयार किया गया. महानदी कोलफील्ड्स के बसुंधरा क्षेत्र में 'कचरे से कला' प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों को अपशिष्ट वस्तुओं से उपयोगी कलाकृतियाँ बनाने हेतु प्रेरित किया गया. ईस्टर्न कोलफील्ड्स के सतग्राम क्षेत्र में 'कबाड़ से सेवा' पहल के तहत बंद अस्पताल की उपयोगी सामग्री समाजसेवी संस्था भारत सेवाश्रम संघ को दान की गई. स्वतंत्रता के बाद पहली बार, 11 कोयला खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद किया गया. कोयला नियंत्रक संगठन ने सतत खनन और हरित वित्त पोषण के लिए लाइव्स और अर्था नामक रूपरेखाएं शुरू कीं.

गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित एनएफआरए का नया टूलकिट

नयी दिल्ली, 03 नवंबर. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने भारत में लेखापरीक्षा प्रथाओं की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा अभ्यास टूलकिट जारी किया है, जो छोटे और मध्यम आकार की लेखापरीक्षा फर्मों को अपने कार्य में सटीकता और पारदर्शिता लाने में सहायता करेगा. एनएफआरए की इस पहल का उद्देश्य लेखापरीक्षा कार्य को अधिक व्यवस्थित, प्रमाणिक और जोखिम-संवेदनशील बनाना है. टूलकिट में ऑडिट प्रक्रिया की चरणबद्ध दिशा-निर्देश, दस्तावेजीकरण के नमूने, और जोखिम मूल्यांकन की विधियां शामिल की गई हैं.

स्टील सेक्टर में हाइड्रोजन क्रांति

अगले 5-10 साल में हाइड्रोजन लेगा प्राकृतिक गैस की जगह

'डीआरआई + हाइड्रोजन' मॉडल को बताया ग्रीन स्टील का भविष्य

नई दिल्ली, 4 नवंबर. केंद्रीय इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक ने मंगलवार को कहा कि स्टील क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन अभियान में हाइड्रोजन अगले 5-10 वर्षों में प्राकृतिक गैस का स्थान ले लेगा, क्योंकि इसकी कीमतें तेजी से गिर रही हैं.

उन्होंने 'डीआरआई प्लस हाइड्रोजन' मार्ग को ग्रीन स्टील उत्पादन के लिए सबसे आशाजनक बताते हुए इसे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और स्थिरता लक्ष्यों का केंद्र बताया.सीआईआई स्टील समिट 2025 में मुख्य भाषण देते हुए पौंड्रिक ने कहा कि रक्षा,

ऑटोमोटिव और बिजली जैसे क्षेत्रों से बढ़ती मांग के कारण इस्पात उद्योग में निवेश के व्यापक अवसर हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय स्टील का 47 प्रतिशत उत्पादन लगभग 2,200 मध्यम और छोटे उद्यमों द्वारा किया जाता है, जो इस इकोसिस्टम की रीढ़ हैं.

टाटा स्टील के कौशिक चटर्जी ने 2030-31 तक 300 मिलियन टन और 2047 तक 500 मिलियन टन के लक्ष्यों को दोहराते हुए स्टील को राष्ट्रीय लचीलेपन की रीढ़ बताया.

आत्मनिर्भरता और लक्ष्य

आत्मनिर्भरता के लिए, मंत्रालय घरेलू कोकिंग कोल की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु कोयला मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है. साथ ही, सरकार सस्ती और निम्न-मानक स्टील की बाढ़ को रोकने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू कर रही है, जिससे समान गुणवत्ता मानक सुनिश्चित हों.विकसित भारत के विजन के तहत, 2047 तक 500 मिलियन टन क्षमता का लक्ष्य है. पौंड्रिक ने कहा कि वर्तमान गति से, भारत हर 5-7 वर्षों में 100 मिलियन टन क्षमता जोड़ रहा है, जिससे वह घरेलू मांग को पूरा करते हुए टिकाऊ स्टील उत्पादन में एक वैश्विक नेता बनेगा.

मॉयल ने स्थापना के बाद सर्वश्रेष्ठ अक्टूबर माह का उत्पादन किया

महाराष्ट्र, 04 नवम्बर. मॉयल ने अक्टूबर 2025 में 1.60 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन दर्ज करते हुए कंपनी के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ अक्टूबर माह का उत्पादन हासिल किया. यह इस अवधि के पिछले वर्ष की तुलना में 9.1% अधिक है.

वर्ष 2025-26 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान कंपनी का कुल उत्पादन 11.04 लाख टन रहा, जो गतवर्ष के समान अवधि की तुलना में 8.5% अधिक है. यह निरंतर उत्पादन वृद्धि कंपनी के संचालन और उत्पादन प्रबंधन में सुधर का संकेत है. मॉयल ने उत्पादन के साथ-साथ अन्वेषण गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया है. अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान कंपनी ने कुल 57,275 मीटर ड्रिलिंग कराई, जो अब तक की सर्वाधिक अन्वेषण ड्रिलिंग मानी जा रही है. अन्वेषण व उत्पादन दोनों क्षेत्रों में सुधार का सीधा लाभ कंपनी की समग्र क्षमता और रिजर्व पहचान में दिखाई देगा.

संजय कुमार की स्पाइसजेट में वापसी

नयी दिल्ली, 04 नवंबर. स्पाइसजेट ने अपने नेतृत्व दल को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विमानन क्षेत्र के अनुभवी पेशेवर संजय कुमार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है. इंडिगो में शीर्ष पदों पर लंबे समय तक सेवाएँ देने वाले कुमार अब स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को सीधे रिपोर्ट करेंगे. उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब कंपनी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है और नए व्यावसायिक रास्तों की तलाश में है.

एनबीसीसी को प्राप्त हुआ सम्मानित पुरस्कार

नई दिल्ली, 4 नवंबर. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के अधीन आने वाले नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 17वें गृहा समिट में दो प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया.

कंपनी को इसकी महत्वपूण ंपरियोजनाओं - वाणिज्य भवन और कौशल भवन के लिए गृहा 5-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई. समिट के दौरान शील्ड के रूप में प्रदान किए

गए रेटिंग पुरस्कारों को के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एव ंप्रबंध निदेशक,एनबीसीसी ने श्रीनिवास कटिकिथला,सचिव,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त किए . इस कार्यक्रम में एनबीसीसी को गृहा के साथ साझेदारी करने के लिए भी सम्मानित किया गया. गृहा परिषद का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, श्री महादेवास्वामी ने भारत के निर्मित पर्यावरण मे ंसंधारणीयता को बढ़ावा देने में संगठन के सुदृढ़ योगदान की सराहना की.

समाचार विशेष

तेजस्वी को पंक्चर कर रहे हैं राहुल!

पटना. महागठबंधन में सीट बंटवारे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिए जाने के बाद राहुल गांधी प्रचार के लिए बिहार पहुंचे. उन्होंने बुधवार, 29 अक्टूबर को दो जनसभा की, जिसमें तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे. इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है. लेकिन थोड़ी बारीकी से देखने पर साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा अभी पूरा नहीं हुआ है.

तीन महीने तक गठबंधन की घोषणा, सीट बंटवारा और तेजस्वी के नाम की घोषणा अटका कर रखने के बाद भी कांग्रेस इस चुनाव में राजद को पंक्चर करने में लगी है. लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को जैसी हैसियत दिखाई है उससे भी कांग्रेस के नेता भड़के हैं. तभी महागठबंधन का घोषणापत्र जब 'तेजस्वी प्रण' के नाम से जारी हुआ तो वहां न तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे और न कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू थे.

बाद में जब राहुल गांधी प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने 'तेजस्वी प्रण' के बारे में कुछ नहीं कहा. तेजस्वी की सबसे महत्वाकांक्षी घोषणा हर परिवार को एक सरकार नौकरी देने की है. इस बारे में राहुल और कांग्रेस के दूसरे नेता चुप्पी साधे हुए हैं. तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को फाड़ कर फेंकने की बात कही है लेकिन राहुल गांधी चुप हैं.

राहुल ने जान बूझकर जिक्र किया

बहरहाल, राहुल गांधी कैसे तेजस्वी यादव को पंक्चर कर रहे हैं इसकी एक मिसाल यह है कि उन्होंने तेजस्वी के सामने कहा कि, 'देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी के यहां शादी में मैं नहीं गया, लेकिन नरेंद्र मोदी गए'. उस समय तेजस्वी यादव का चेहरा देखने लायक था. क्या राहुल को पता नहीं था कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित परिवार के करीब एक दर्जन सदस्य उस शादी में गए थे? निश्चित रूप से राहुल को पता होगा कि पूरा लालू परिवार विशेष विमान से शादी में गया था, वहां अगली पंक्ति में बैठा था और फोटो खिंचवाने की जगह पर खड़े होकर सबने तस्वीरें खिंचवाई थी.

प्रचार नहीं करूंगी, लेकिन आशीर्वाद साथ

पटना. बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पहली बार अपने बेटे तेज प्रताप यादव पर सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट की.

उन्होंने कहा कि वह दिल से मेरा बेटा है, इन लोगों ने उसे पार्टी और घर से निकाल दिया है. मैं प्रचार नहीं करूंगी, लेकिन चाहती हूं कि वह चुनाव जीते. उन्होंने आगे कहा कि वह अपने पैरों पर खड़ा है और उसे बिहार में काम करने का पूरा अधिकार है.

तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच चल रहे राजनैतिक मतभेदों के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई-बहन एक जैसे होते हैं. जिनके घर नहीं होते, वही दूसरों के घरों में झगड़ा लगवाते हैं.

राबड़ी देवी ने कहा कि जब एक गरीब के बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया लोगों को उनके हक मिलने लगे तो उसे जंगल राज कहा गया था. लेकिन अब, जब मोकामा और आरा में हत्याएं हो रही हैं, तो क्या इसे भी जंगल राज कहा जाएगा?

लड्डुओं की मिठास और सियासी खटास

पटना. बिहार की राजनीति में पटना जिले की मनेर विधानसभा सीट एक अनूठी पहचान रखती है. गंगा और सोन नदियों के पवित्र संगम पर बसा यह क्षेत्र, अपने प्रसिद्ध 'मनेर के लड्डू' की मिठास के साथ-साथ, पिछले एक दशक से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए एक मजबूत और अभेद्य किला बन चुका है. पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यह सीट पूरी तरह से यादव समुदाय के वर्चस्व और कड़े राजनीतिक समीकरणों पर टिकी हुई है.

राजद का अभेद्य किला मनेर- मनेर की राजनीति में दल-बदल का इतिहास रहा है, लेकिन पिछले एक दशक से यहां राजद का दबदबा कायम है. राजद के दिग्गज नेता भाई वीरेंद्र इस सीट से लगातार तीन बार (2010, 2015, 2020) जीत दर्ज कर चुके हैं और 2025 में जीत का चौका लगाने की तैयारी में हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के निखिल आनंद को 32,917 वोटों के बड़े अंतर से हराकर अपनी पकड़ की मजबूती

साबित की थी. मनेर सीट पर यादव समुदाय का वर्चस्व रहा है, और राजद ने इस वोट बैंक को सफलतापूर्वक साधकर ही लगातार जीत हासिल की है, जिससे यह पार्टी का गढ़ बन गई है.

2024 लोकसभा का संकेत- मनेर का मजबूत राजनीतिक आधार सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है. 2009 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इसी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से हार मिली थी, लेकिन उनकी बेटी मीसा भारती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके इस क्षेत्र में पार्टी की उपस्थिति को फिर से मजबूत किया.2024 के लोकसभा चुनाव में मनेर विधानसभा क्षेत्र ने राजद को 34,459 वोटों की बड़ी बढ़त दी, जो आगामी नवंबर महीने के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की मजबूत स्थिति का स्पष्ट संकेत है.

मनेर का इतिहास और सांस्कृतिक विरासत

मनेर की पहचान इसके राजनीतिक समीकरणों से कहीं ज्यादा गहरी है. प्राचीन काल में इसे 'मनियार मठान' यानी 'संगीतमय नगरी' के नाम से जाना जाता था. माना जाता है कि संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना 'अष्टाध्यायी' की रचना से पहले यहीं अध्ययन किया था. आज मनेर शरीफ 13वीं सदी के सूफी संत मखदूम याह्या मनेरी और 16वीं सदी के मखदूम शाह दौलत की दरगाहों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे इस्लामी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनाता है.

विशेष | भाजपा के सामने सीट बचाने की चुनौती

आरक्षण के बाद बदला सियासी समीकरण

पटना. बांका जिले की कटोरिया विधानसभा सीट (अनुसूचित जनजाति आरक्षित) इस बार चुनावी दृष्टि से विशेष महत्व रखती है. झारखंड की सीमा से सटे पहाड़ी क्षेत्र और छोटानागपुर पठार का हिस्सा होने के कारण यह सीट अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए जानी जाती है.

2008 में आरक्षित होने के बाद यहां का चुनावी परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया, और अब यह सीट भाजपा और राजद के बीच कड़े मुकाबले का केंद्र बन चुकी है.

आरक्षण के बाद भाजपा-राजद की सीधी टक्कर- कटोरिया सीट का इतिहास बताता है कि 2008 में एसटी के लिए आरक्षित होने से पहले यहां कांग्रेस का दबदबा था, जिसने 5 बार जीत दर्ज की थी. आरक्षण के बाद मुकाबला सीधे तौर पर राष्ट्रीय दलों के बीच आ गया, जहां भाजपा और राजद ने अपनी पकड़ मजबूत की है. पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की निक्की हेम्ब्रम ने राजद की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को हराकर जीत हासिल की थी. यह हार-जीत का सिलसिला 2025 में भी जारी रहने वाला है.

स्वीटी सीमा हेम्ब्रम पर आरजेडी का भरोसा- इस बार भाजपा ने पूरन लाल टुडू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि राजद ने पिछली बार की मजबूत दावेदार स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को फिर से मैदान में उतारा है. इसके अलावा, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सलोनी मुर्मू को टिकट देकर चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है. चूंकि सभी प्रमुख उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति (स्ज्ञ) से आते हैं, इसलिए गैर-आदिवासी वोटों (जैसे मुस्लिम, भूमिहार, कोइरी) की दिशा इस बार निर्णायक साबित हो सकती है.

कटोरिया सीट का जातीय समीकरण- कटोरिया एसटी आरक्षित सीट होने के बावजूद, यहां के चुनावी नतीजे में गैर-आदिवासी समुदायों का वोट विभाजन महत्वपूर्ण है. मुस्लिम और सवर्ण वोटर हार-जीत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं का पारंपरिक झुकाव महागठबंधन की ओर रहा है.

इतिहास, धर्म और आस्था का केंद्र

कटोरिया क्षेत्र अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है. बौंसी में स्थित मधुसूदन मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख केंद्र है. वहीं, राधानगर बाजार स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में पिछले 136 वर्षों से मां भगवती को डाक चढ़ाने की परंपरा आज भी जारी है. चांदन नदी पर स्थित लक्ष्मीपुर गांव का उल्लेख राजा लक्ष्मीपुर की पूर्व सीट के रूप में किया जाता है, जिनके किले के अवशेष आज भी मौजूद हैं.